जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी
Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 108 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 20 फरवरी, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

यह राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है- मुख्यमंत्री भजनलाल

सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन एनर्जी, रीसाइक्लिंग के लिए कुल राज्य बजट में 11.34 प्रतिशत राशि का प्रावधान

जयपुर, 19 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और राज्य की जनता से संकल्प पत्र में किये गये वादों के अनुसार राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58 प्रतिशत से अधिक वादे पूरे कर दिये हैं।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष जुलाई में प्रस्तुत परिवर्तित बजट में 96 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं में भूमि आवंटन हो चुका है तथा 85 प्रतिशत में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधान सभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट वर्ष 2025-26 प्रस्तुत किये जाने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि गत जुलाई माह में प्रस्तुत परिवर्तित बजट की 96 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं में हमने भूमि आवंटन कर दिया है तथा लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा घोषणाओं से संबंधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। शर्मा ने कहा कि संभवतया ऐसा पहली बार हुआ है कि सात माह के अल्प समय में ही बजट घोषणाओं को इतने वृहद स्तर पर धरातल पर उतारा गया है।

उन्होंने बजट को जनहित में समर्पित और विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ठोस प्रावधान किए गये हैं, जो राज्य के सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करेंगे। आगामी वर्ष में 20 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार कार्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री घोषित

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 फरवरी। अन्ततोगत्वा दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल ही गया। पहली बार विधायक बनी रेखा भाजपा की सबसे युवा विधायक है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले प्रवेश वर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

- मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे प्रवेश वर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है।

सूत्रों ने कहा कि आर.एस.एस. चीफ मोहन भागवत ने दिल्ली में संघ मुख्यालय में अमित शाह, जे.पी. नड्डा और राजनाथ सिंह को बुलाकर निर्देश दिए थे कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए।

रेखा गुप्ता आर.एस.एस. की हैं। छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई थीं। वे संघ की पसंद हैं। कल शपथ ग्रहण होगा।

इससे स्पष्ट है कि संघ प्रमुख यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत अब डोटासरा का सहारा ले रहे हैं, दिल्ली में अपनी जगह ढूंढने के लिए

पर, जब गहलोत सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत के कारण संकट में आये थे, स्थिति को भांपते हुए डोटासरा ने गहलोत से बचना शुरू किया था

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 फरवरी। एक रोचक मोड़ के अन्तर्गत, अशोक गहलोत एक बार फिर अपने अच्छे मित्र गोविन्द सिंह डोटासरा, जो राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, के जरिये दिल्ली के मन की थाह ले रहे हैं।

अगर सचिन पायलट दिल्ली में मीडिया को लंच की दावत दे सकते हैं, तो क्या अशोक गहलोत पीछे रह सकते हैं? दिल्ली में सचिन पायलट के लंच (जो संयोगवश एक वार्षिक आयोजन है) से एक दिन पहले, डोटासरा ने दिल्ली मीडिया के लिए लंच का आयोजन किया। यह आयोजन पहली बार ही हुआ है।

समझा जाता है कि इसके मुख्य आयोजक डोटासरा के पुत्र अभिलाष थे, जिन्होंने प्रशान्त किशोर की आई पैक के साथ काम किया है तथा इस समय दिल्ली में उनकी पहचान एक लॉबीइस्ट (लामबन्दी करने वाले) के रूप में है। वे अपनी पूरी ऊर्जा दो कामों में लगा रहे हैं - सबसे पहले तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पिता राजस्थान पी सी सी अध्यक्ष बने रहें, तथा दूसरी बात यह कि वे राहुल एवं प्रियंका की टीम से सम्पर्क बनाये रखना चाहते हैं ताकि राहुल और प्रियंका तक पहुंच के

- पर दोनों के (डोटासरा व गहलोत) रिश्ते ज्यादा दिन टूटे नहीं रहे, तत्कालीन मु.मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा मंत्री डोटासरा को बचाया पेपर लीक काण्ड में।
- जैसा, कि विदित ही है, डोटासरा परिवार के तीन सदस्यों को पेपर में एक दम बराबर मार्क्स मिले थे। तथा, यह पेपर लीक काण्ड सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था।
- दिल्ली के राजनीतिक हल्कों में चल रही चर्चाओं के अनुसार, हाईकमान की गहलोत के प्रति नाराज़गी में कोई कमी नहीं आई है, तथा, कुछ समय बाद पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजा जायेगा, कांग्रेस संगठन को विधानसभा चुनाव तक पूरी तरह ''फाइटिंग फिट'' बनाने के लिए।
- इस सम्भावना ने डोटासरा व गहलोत को और करीब ला दिया है, तथा एक सुनियोजित रणनीति के तहत पायलट के, दिल्ली में मीडिया के लिए आयोजित वार्षिक भोज से एक दिन पहले डोटासरा-गहलोत ने भी डोटासरा की ओर से पहली बार प्रदेशाध्यक्ष की हैसियत से मीडिया के लिए एक लंच आयोजित करवाया दिल्ली में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा व कांग्रेस में एक बार फिर भारी भिड़न्त

इस बार मुद्दा है, अमेरिका द्वारा भारत को ''वोटर टर्न आऊट'' बढ़ाने के प्रयासों के लिए 21 करोड़ डॉलर का अनुदान

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। भारत को दी जाने वाली 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यूएस एड ग्रांट को रद्द करने के अमेरिकी सरकार के निर्णय ने कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एंट्री भी हो गई है।

कांग्रेस के अनुसार, अब तो सच सामने आ ही गया है, क्योंकि श्रीमती ईरानी 'भारत में यूएस एड की सद्भावना एम्बेसडर' के रूप में कार्य कर चुकी हैं। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने पूछा, ''क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा के नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट थे?' सोरोस का उल्लेख दिलचस्प है: क्योंकि इस अरबपति पर आरोप है कि उसे दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने के लिए यूएस एड ग्रांट्स मिलीं हैं।''

कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी

- कांग्रेस का आरोप है ''यू.एस. एड'' अनुदान वाली संस्था की भारत में गुडविल एम्बेसेडर (सद्भावना राजदूत), स्मृति इरानी थीं।
- कांग्रेस का यह भी आरोप है, कि, विदेश मंत्री जयशंकर व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के शासन काल में, यू.एस. एड के काम की सराहना करते हुए कई बार यू.एस. एड कामकाज का समर्थन किया है।
- दूसरी ओर, भाजपा ने कहा 2012 में, यू.पी.ए. सरकार के शासन काल में मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाय. कुरैशी ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसायटी फाउण्डेशन से अधिकृत अनुबन्धन किया, तथा, यह संस्था भारत विरोधी तत्वों को, जो कांग्रेस से सम्बद्ध हैं, की फण्डिग करती थी। यह भी कहा भाजपा ने कि यह शोध व छानबीन का विषय है, कि क्या यू.एस. एड व जॉर्ज सोरोस राजीव गांधी फाउण्डेशन व राजीव गाँधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे देते थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कोई भी मुझ से बहस नहीं कर सकता'

-डा. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। एक अरबपति एलन मस्क के साथ टीवी पर प्रसारित एक इंटरव्यु में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वार्ता का हवाला देते हुए कहा, ''कोई भी मुझ से बहस'' नहीं कर सकता।

ट्रम्प ने साफ कर दिया कि ''रैसिप्रोकल टैरिफ'' (जितना टैरिफ कोई देश अमेरिकन सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ उस पर लगाएगा) से भारत को भी बख्शा नहीं जाएगा। फॉक्स न्यूज़ के सीन हैनरी के साथ बात करते हुए ट्रम्प ने ग्लोबल ट्रेड

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह कहा, मैंने मोदी से साफ कह दिया, आप जो चार्ज करेंगे मैं भी वहीं चार्ज करूंगा। मोदी ने कहा, यह ठीक नहीं, पर मैंने कह दिया नहीं आप जो टैक्स लेंगे मैं भी वहीं लूंगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, उसे वित्तीय अनुदान की जरूरत नहीं'

ट्रम्प ने ''वोटर टर्न आऊट'' बढ़ाने के लिए भारत को दिये जा रहे 21 करोड़ डॉलर के अनुदान को बंद करने की घोषणा की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ''गर्वनमैंट एफिशिएंसी'' विभाग, जिसके मुखिया अरबपति एलन मस्क हैं, के भारत को 21 मिलियन डॉलर की मदद बंद करने के निर्णय का समर्थन किया। यह मदद भारत में मतदाताओं का मतदान के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा एक भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है उसे वित्तीय मदद की जरूरत नहीं है।

अपुष्ट रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूर्ण सम्मान दर्शाया, पर, ''वोटर टर्न आउट'' के लिए आर्थिक मदद देने के आइडिया की आलोचना की।

ट्रम्प ने कहा, हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे है। विश्व में हम पर सर्वाधिक टैक्स लगाने वाला देश भारत है। टैक्स इतना ज्यादा है कि हमारा सामान वहाँ बिक ही नहीं पाता है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर, हम वोटर टर्न आउट के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं?

ट्रम्प ने नए विभाग ''गर्वनमैंट एफिशिएंसी'' का दारोमदार गत माह ही एलन मस्क को सौंपा था। इस विभाग का काम सुशासन बढ़ाना और फालतू खर्च कम करना है। इस विभाग ने 15 फरवरी को एक्स पर ऐसे कई सहायता कार्यक्रम कैंसल करने की घोषणा की थी।

विभाग ने कहा, इन कार्यों पर अमेरिकन करदाता का पैसा खर्च हो रहा है और अब इन्हें बंद किया जाता है।

इस लिस्ट में 486 मिलियन डॉलर की सहायता शामिल है जो ''कंसोर्टियम फॉर इलैक्शन एण्ड पॉलिटिकल प्रोसैस स्ट्रेंथनिंग'' के लिए दी जाती है। इसके तहत वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं और मॉल्डोवा को समावेशी और भागीदारी राजनैतिक प्रक्रिया के लिए 22 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं। पोस्ट में अन्य फंडिंग का ब्यौरा नहीं है।

यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ ही दिन बाद उठाया गया है। अमेरिका यात्रा में मोदी ने ट्रम्प से ही नहीं मस्क से भी मुलाकात की थी।

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा आईटी सैल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे भारत के चुनावों में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने कहा, ''वोटर टर्न

- ट्रम्प ने साथ में यह भी कहा, कि, मैं भारत के प्र.मंत्री मोदी का आदर करता हूँ, भारत को ''वोटर टर्न आऊट'' बढ़ाने के लिए दिये गये अनुदान का सख्त विरोध करता हूँ।
- ट्रम्प के अनुसार, ''भारत उन देशों की सूची में है, जो सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं, विशेषकर अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर। उनका टैरिफ इतना अधिक है, कि, हम (अमेरिका) तो वहां घुस ही नहीं पाते।
- वरिष्ठ भाजपा नेता अमित मालवीया ने कहा, यह जानने की जरूरत है, कि इस अनुदान से भारत में कौन ''लाभान्वित'' हुआ।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होली के बाद होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की सुनवाई

नई दिल्ली, 19 फरवरी। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों के खिलाफ दायर

- हालांकि, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी, पर अब सुनवाई टाल दी गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प व मस्क पहली बार टकराहट की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, ''इलैक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग'' को लेकर!

मस्क अपनी ''इलैक्ट्रिक कार'' टैस्ला के लिए भारत में कारखाना लगाना चाहते हैं, पर ट्रम्प की घोषित नीति के तहत यह प्लॉन्ट अमेरिका में लगना चाहिए।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 फरवरी। भारत में टैस्ला का, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रोजेक्ट अब थोड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इस समय कंपनी के सबसे बड़ा समर्थक, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प, इसे अमेरिका के लिए ''अन्यायपूर्ण'' कदम मान रहे हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि टैस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन अमेरिका में बनें और भारत को निर्यात किए जाएं।

इसके बजाय, एक पक्के व्यवसायी के तौर पर एलन मस्क स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क, भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस से कुछ क्षेत्रीय बाजारों को भी सेवा देना चाहते हैं।

ऐसा इसलिए, क्योंकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में बने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रीय बाजारों और भारत में प्रवेश के लिए काफी महंगे पड़ेंगे। इसके अलावा, यह कदम, उत्पाद इकाइयों द्वारा ''अमेरिका को फिर से महान बनाने'' के ट्रंप के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ भी है।

तथापि, ट्रम्प अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। अमेरिका ने कई मैन्युफैक्चरिंग बेस और आपूर्ति श्रृंखलाएं खो दी हैं, जो विभिन्न वस्तुओं के कुशल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक थीं। यह, मैन्युफैक्चरिंग के एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर पलायन की बस एक प्रक्रिया है। एक बार जब कोई देश एक निम्न स्तर की गतिविधि की स्पेस को छोड़ देता है, तो उसे फिर से उस स्पेस में वापस लौटना मुश्किल होता है।

दूसरी तरफ, भारत को देश में, संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आवश्यक सभी कॉम्पोनैंट्स के निर्माण के काम में जुटना होगा। इस उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि उत्पाद की अंतिम लागत कॉस्ट-इफैक्टिव हो सके।

तथापि, इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रम्प से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

दरअसल, कुछ मीडिया हाउस यह बता रहे हैं कि ट्रंप व मस्क, दोनों के हित स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी हैं। एलन मस्क एक व्यवसायी हैं और उनके बड़े व्यापारिक हित उनकी प्राथमिकता हैं।

यहां तक कि मस्क, ट्रम्प से कहीं बड़े उद्योगपति हैं, और यह बात उनके पसंदीदा टेलीविजन चैनल, फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में जाहिर हुई। इन्टरव्यू लेने वाले ने साफ कहा कि मस्क सबसे अमीर आदमी हैं और संपत्ति के मामले में ट्रम्प उनसे बहुत पीछे हैं। ट्रम्प ने इसे नज़रअंदाज़ किया, हालांकि, यह बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।

तथापि, मस्क ट्रम्प के लिए एक उपयोगी सहायक साबित हो रहे हैं, क्योंकि मस्क ट्रम्प के कार्यकारी आदेशों को लागू करने के लिए टैक्नॉलजी इनपुट्स मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। हो यह रहा है, कि कार्यकारी आदेशों को प्रभावी ढंग से तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन आदेशों की क्रियान्विति की

- मस्क का इरादा है, इण्डिया के कारखाने में निर्माण करके वे एशिया अफ्रीका आदि क्षेत्रों में अपनी टैस्ला कार सस्ते दामों में बेच सकेंगे।
- ट्रम्प का सोच है, अगर, टैस्ला कार अमेरिका होकर विश्व भर में भेजी जाये, तो अमेरिका ज्यादा समृद्ध होगा व अमेरिका में रोजगार भी ज्यादा उपलब्ध होंगे।
- मस्क का सोच ज्यादा व्यवहारिक लगता है, क्योंकि, हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे कालान्तर में किफायत से काम करने की तकनीक विकसित हो गई है, अतः भारत में निर्मित टैस्ला, अमेरिका में निर्मित टैस्ला से ज्यादा सस्ती होगी।
- मस्क का मानना है, जैसा, कि, उन्होंने हाल ही में अपने फेवरेट टी.वी. चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिये इन्टरव्यू में जताया कि ट्रम्प की तुलना में मस्क कहीं ज्यादा बड़े व सफल उद्योगपति हैं, अतः उनकी सोच मानी जानी चाहिए।
- ट्रम्प को मस्क का यह बड़बोलापन कतई पसन्द नहीं आया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. भर्ती पेपर लीक पर सुनवाई गुरूवार को होगी

जयपुर, 19 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है।

याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका बुधवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से सुबह ही अदालत को जानकारी दी गई कि प्रकरण में उच्च स्तर पर

- अतिरिक्त महाअधिवक्ता विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि प्रकरण में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है, अतः सुनवाई गुरूवार तक टाल दी जाये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)